



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

17 पौष 1936 (श0)

(सं0 पटना 25)

पटना, बुधवार, 7 जनवरी 2015

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

22 अक्टूबर 2014

सं0 22/नि0सि0(पट0)—03—12/2012/1558—मो0 इदरीश, तत्कालीन अवर प्रमण्डल पदाधिकारी, नौबतपुर सम्प्रति निलंबित जब (07.02.96 से 07.08.98 तक) अवर प्रमण्डल पदाधिकारी, नौबतपुर के पद पर पदस्थापित थे तब उनके विरुद्ध जल संसाधन विभाग की बहुमूल्य सरकारी जमीन का फर्जी दस्तावेज तैयार कर सरकारी जमीन के अतिक्रमण करने में एवं उक्त जमीन पर बहुमंजिली इमारत निर्माण करने में अन्तर्लिप्त रहने, फर्जी दस्तावेज को सच्ची प्रतिलिपि मानकर उक्त जमीन की वर्ष 1991-92 से 98-99 तक रसीद काटने के प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोपो के लिए विभागीय अधिसूचना संख्या 1107 दिनांक 11.10.2012 द्वारा उनको निलंबित करते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक 14 दिनांक 07.01.2013 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 के तहत विभागीय कार्यवाही चलायी गयी।

संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी। संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोप प्रमाणित नहीं पाया गया। परन्तु मामले की विभागीय समीक्षा में पाया गया कि जिस अतिक्रमित भूमि की लीज की रसीद उनके द्वारा काटा गया है वह सही लीज है अथवा नहीं इसकी जानकारी प्राप्त नहीं की गई, जबकि वर्तमान में तथाकथित लीज डीड के अवलोकन से स्पष्ट है कि इस पर किसी सक्षम पदाधिकारी का हस्ताक्षर नहीं है। दस्तावेज में वर्ष का उल्लेख नहीं किया गया है, फिर भी उनके द्वारा फर्जी दस्तावेज को सच्ची प्रतिलिपि के रूप में ग्राह्य करते हुए रसीद काटी गयी।

वर्णित स्थिति में उनके द्वारा बिना किसी छान-बीन के और बिना अपने उच्चाधिकारियों के आदेश प्राप्त किये रसीद काटने एवं अपनी स्वार्थ सिद्धि को पूर्ण करने का आरोप प्रमाणित पाया गया।

वर्णित स्थिति में समीक्षोपरान्त विभागीय पत्रांक 102 दिनांक 20.01.14 द्वारा जाँच प्रतिवेदन से निम्नांकित असहमति के विन्दु पर द्वितीय कारण पृच्छा किया गया:—

विभागीय भूखण्ड के लीज को प्रमाणिकता के बिना जाँच किये ही आपके द्वारा लीज रेंट की वसूली की गई जबकि लीज कागजात फर्जी थे अतएव विभागीय बहुमूल्य भूखण्ड का बिना किसी प्रमाण के आधार पर गलत ढंग से रेंट रसीद निर्गत कर विभाग को भूखण्ड से बेदखल करने की साजिश में आपकी संलिप्तता प्रमाणित होती है।

मो0 इदरीश द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा की समीक्षा विभाग द्वारा की गई। पाया गया कि श्री इदरीश द्वारा अपने द्वितीय कारण पृच्छा के जबाव में कहा गया है कि श्री पी0 आर0 गुहा, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, डिहरी प्रमण्डल, डिहरी के द्वारा दिनांक 3.3.47 को Home Street Land के लिए कैडेस्टल सर्वे 118 का 24 डी0

भूखण्ड मोहिउद्दीन खॉ पिता स्व० गुलाब खॉ, करबिगहिया, पटना के नाम पर वर्ष 1943-46 से 1946-49 के लीज पर दी गई। इस लीज डीड में अंकित लीज रेन्ट के आधार पर वर्ष 1943 से ही मनी रसीद निर्गत किया जाता रहा है। इससे साबित हो जाता है कि लीज कागजात फर्जी नहीं थे। रेन्ट का मनी रसीद निर्गत कर विभाग का स्वामित्व इस भूखण्ड पर बरकरार रखा गया।

समीक्षा में पाया गया कि मो० इदरीश द्वारा अपने द्वितीय कारण पृच्छा में स्वयं स्वीकार किया गया है कि तथाकथित लीज को समाप्त करने के लिए कार्यपालक अभियन्ता द्वारा वर्ष 2012-13 में वाद दायर किया गया था। उल्लेखनीय है कि सरकार द्वारा इस भूमि का लीज पर दिये जाने की कोई न तो अनुमति दी गई और न ही स्वीकृति दिया गया था। इससे स्पष्ट है कि श्री इदरीश द्वारा अपने द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब में कोई नया तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसलिए इनके विरुद्ध तथाकथित लिज को बिना जाँच पड़ताल के रेन्ट रसीद काटने का आरोप प्रमाणित पाया गया। वर्णित तथ्यों के आलोक में अवैध कार्य में इनकी संलिप्ता की पुष्टि होती है। वर्णित स्थिति में उन्हें निलंबन से मुक्त करते हुए प्रमाणित आरोपों के लिए सरकार द्वारा निम्न दण्ड देने का निर्णय लिया गया:-

1. कालमान वेतन के दो वेतन प्रक्रम से नीचे सदैव के लिए अवनति।

2. निलंबन अवधि की सेवा का निरूपण एवं वेतनभत्ता के संबंध में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 11 (5) के तहत नोटिस निर्गत किये जाने एवं नोटिस के आलोक में प्राप्त अभ्यावेदन के समीक्षोपरान्त निर्णय लिया जायेगा।

उपरोक्त वर्णित स्थिति में मो० इदरीश, तत्कालीन अवर प्रमण्डल पदाधिकारी, नौबतपुर सम्प्रति निलंबित को तत्काल प्रभाव से निलंबन से मुक्त करते हुए निम्न दण्ड दिया एवं संसूचित किया जाता है:-

1. कालमान वेतन के दो वेतन प्रक्रम से नीचे सदैव के लिए अवनति।

2. निलंबन अवधि की सेवा का निरूपण एवं वेतनभत्ता के संबंध में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 11 (5) के तहत नोटिस निर्गत किये जाने एवं नोटिस के आलोक में प्राप्त अभ्यावेदन के समीक्षोपरान्त निर्णय लिया जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
सतीश चन्द्र झा,  
सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 25-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>